जबलपुर | रविवार | 30 अगस्त 2026 | वर्ष 77 | अंक 217 | पृष्ठ 12 | मूल्य रु. 5.00
navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 डिजिटल दौड़ में जियो आगे, लेकिन विकल्प कितने बाकी?

6 निर्विकल्प से निराकार की साधना

7 15 साल बाद रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी

8 चोट के कारण नीरज एशियाई खेलों से बाहर

प्राधिकरण के जरिए होगा बैगाओं का विकास

जन विश्वास अभियान के तहत सीएम ने की गठन की घोषणा

- 225 करोड़ में होगा 100 गांवों का कायाकल्प
- बालाघाट जिले में मंत्रियों के लगातार दौरे होंगे

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, बालाघाट 29 अगस्त. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को जन विश्वास अभियान के सिलसिले में बालाघाट जिला पहुंचें.

यहां उन्होंने बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की बड़ी घोषणा की. जिले में गौंड और बैगा जनजाति समुदाय की बड़ी आबादी है. वहीं सीएम ने जिले के ऐसे 100 गांव जो कि विकास की दौड़ में अब भी पिछड़े हुए हैं और कभी नक्सलियों के प्रभाव में भी रहे, उन के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया. साथ ही भरोसा दिलाया कि इन क्षेत्रों में प्रदेश के मंत्रियों के दौरे का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, जिससे कि विकास के कामों पर कड़ी नजर रखी जा सके. बाद में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लांजी में मीडिया से भी बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने बालाघाट जिले में नक्सलवादी गतिविधियों को जड़ से खत्म कर दिया है. आज हमारा प्रशासन और अधिकारी उन इलाकों तक पहुंचे हैं, जहां बीते कई सालों तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया. बालाघाट जिला वह क्षेत्र रहा है, जहां नक्सलियों ने दिसंबर 1999 में तत्कालीन सरकार के मंत्री की निर्मम हत्या कर दी थी. अब सरकार नक्सलमुक्त हो चुके इन क्षेत्रों में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है.

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर होगा पूरा फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बैगा समुदाय की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए बैगा विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी. इस प्राधिकरण से बैगा समुदाय के लिए सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना विकास के कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बैगा समुदाय को शिक्षा, आजीविका और कौशल विकास के साथ जोड़कर उन्हें भरपूर लाभ दिया जाएगा.

सभी दलों को साथ लेकर होंगे विकास कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बालाघाट और लांजी क्षेत्र के विकास के लिए हमने विपक्ष के निर्वाचित विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी साथ लेकर क्षेत्र के विकास की योजना तैयार की है. आने वाले समय में हम नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों को भी साथ लेकर क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करेंगे. जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित राज्य सरकार के अन्य मंत्रियों को भी बालाघाट जिले के दौरे पर भेजा जाएगा.

शाह के सामने रखा विकास का खाका

सीएम ने मुलाकात कर दी प्रदेश की समग्र जानकारी

नई दिल्ली, 29 अगस्त. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की. मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अमित शाह को मध्यप्रदेश में संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और वर्तमान स्थिति से के बारे में जानकारी दी.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों, नए प्रयासों और उपलब्धियों की भी जानकारी दी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में संचालित विकास योजनाओं और राज्य के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की ताजा स्थिति पर भी केंद्रीय मंत्री शाह से चर्चा की. इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से प्रदेश के विकास को और गति देने के लिए उनका सहयोग और मार्गदर्शन मांगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्यप्रदेश विकास एवं जनकल्याण के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश के विकास की गाथा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना और प्रत्येक नागरिक के जीवन में समृद्धि एवं खुशहाली लाना है.

एक नजर में

दिल्ली में आईएसआई के एजेंट गिरफ्तार

नई दिल्ली. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित तौर पर जासूसी करने वाले एक दंपती को गिरफ्तार कर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के नेटवर्क का खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी वर्ष 2024 से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे.

ममता के खिलाफ एक और केस

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन को लेकर हेस्टिंग्स थाने में ममता बनर्जी और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है.

गाजियाबाद की खिलौना फैक्ट्री में भीषण आग

गाजियाबाद. गाजियाबाद में खिलौना इकाई में आग लगने से हड़कंप मच गया. फैक्ट्री से आग की लपटें और धुआं उठता देखकर आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा.

मंडरा रहा एक और महाप्रलय

नेपाल त्रासदी | 669 मौत अब तक | 2400 से अधिक लोग लापता | 287 भारतीयों की तलाश जारी

नवभारत न्यूज

काठमांडु, 29 अगस्त. नेपाल बाढ़ त्रासदी में 669 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. नेपाल सरकार के मुताबिक 2426 लोग अब भी लापता हैं. प्रभावित इलाकों में तेजी से राहत एवं बचाव कार्य चलाया जा रहा है. विदेश मंत्री ने बताया कि 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं.

नेपाल के विदेश मंत्री शिसिर खनाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 187 विदेशी नागरिकों सहित 4,451 लोगों को बचाया जा चुका है. फिर से बाढ़ आने की संभावनाओं और चिंताओं को देखते हुए खनाल ने कहा कि जोखिम पर नजर रखी जा रही है और क्षेत्र उच्च सतर्कता पर है. उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने का एकमात्र तरीका हेलीकॉप्टर है. कुछ भूभाग दलदली भूमि में बदल गया है, जिसका मतलब है कि हेलीकॉप्टर वहां उतर नहीं सकते. वहीं, बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित नेपाल में फंसे महाराष्ट्र के 100 तीर्थयात्रियों को घर लौटने में की मदद की. काठमांडो में फंसे महाराष्ट्र के 100 तीर्थयात्रियों को बिहार सरकार ने सुरक्षित बाहर निकाला और ट्रेन से उनके गृह राज्य भेजा. नेपाल के दक्षिणी मध्य तराई क्षेत्र के चितवन जिले के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ से अब तक बरामद किए गए 233 शवों में से केवल चार की ही पहचान हो पाई है.

भारतीयों की पहचान के लिए फोरेंसिक दल पहुंचा

भारतीय फोरेंसिक विशेषज्ञों की छह टीमें को काठमांडू पहुंचेगी. ये टीमें मृतकों के अवशेषों की पहचान के लिए डीएनए सैंपल के विश्लेषण में मदद करेंगी. भारत की एक विशेष तकनीकी टीम सुरंग बचाव अभियान की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहले ही काठमांडू पहुंच चुकी है. टीम ने आज से प्रभावित क्षेत्र में काम शुरू किया. तकनीकी टीम की सिफारिश के आधार पर भारत की एक विशेष टनल रेस्क्यू टीम जरूरी उपकरणों के साथ नेपाल पहुंचने वाली है. यह टीम प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से जुड़े बचाव अभियान में सहायता करेगी. नेपाल में प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान के बीच भारत ने चार और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया है.

इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ गोपीसेटी भी लापता

नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भीषण बाढ़ के बाद लापता लोगों की तलाश जारी है. इस आपदा में इंफोसिस

पब्लिक सर्विसेज के सीईओ लक्स गोपीसेटी भी लापता हैं और उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. इंफोसिस ने कहा है कि वह अथॉरिटीज के साथ मिलकर उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रही है और उनके परिवार को हर संभव मदद दे रही है.

5 अरब डॉलर होंगे खर्च

नेपाल के वित्त मंत्री ने अनुमान लगाया है कि विनाशकारी बाढ़ के बाद देश के पुनर्निर्माण के लिए 4 अरब डॉलर से 5 अरब डॉलर के बीच की राशि की जरूरत होगी.

शवों की नहीं हो रही पहचान

स्वास्थ्य संस्थानों और नदी तटों से एकत्र किए गए शव/अवशेष सड़ने की अवस्था में हैं और अब उनकी पहचान करना संभव नहीं हो पा रहा है.

युवाओं के बीच पहुंचने भाजपा का रोडमैप तैयार

पार्टी अध्यक्ष नवीन ने बैठक में किया साझा

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 29 अगस्त. भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को संगठन से जोड़ने और देशभर में इस वर्ग के बीच अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की है.

भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में करीब 45 नेता शामिल हुए. इनमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के उपमुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और युवा नेता शामिल रहे. बैठक में युवाओं के साथ संवाद बढ़ाने और उन्हें संगठन में आगे बढ़ाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया. पार्टी नेतृत्व ने नई पीढ़ी की बदलती सोच, पसंद-नापसंद, मौजूदा परेशानियों और भविष्य को लेकर उनकी उम्मीदों को समझने की जरूरत पर जोर दिया. इसके साथ ही युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने के लिए नए राजनीतिक और संवादात्मक माध्यमों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई.

पार्टी की योजना में सरकार और संगठन के स्तर पर मिलकर काम करने की बात कही गई है. युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों तथा विभिन्न संवाद प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर विचार हुआ. इसका उद्देश्य युवा वर्ग के साथ सीधे संपर्क को बढ़ाना और उन्हें पार्टी की गतिविधियों से जोड़ना है. बैठक में कई राज्यों से पहुंचे नेताओं ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए.

23 लाख का स्टाप डैम महीने भर में बह गया

- बैढ़न के सितुलखुर्द ग्राम पंचायत का मामला
- एसडीओ एवं उपयंत्री भी सवालों के घेरे में

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 29 अगस्त. सरकारी निर्माणों की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला ग्राम पंचायत सितुलखुर्द के नौढ़िया से सामने आया है. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना के तहत विधायक के सहयोग से करीब 23.30 लाख रुपये की लागत से निर्मित स्टापडैम पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होकर ध्वस्त हो गया.

जनपद पंचायत क्षेत्र बैढ़न के ग्राम पंचायत सितुलखुर्द अंतर्गत नौढ़िया के लौआ नदी पर स्टापडैम निर्माण से वर्षों तक ग्रामीणों को सुविधा मिलने की उम्मीद थी, वह महीना भर भी नहीं टिक सका. स्टापडैम के इस तरह टूटने से निर्माण में इस्तेमाल सामग्री, तकनीकी मानकों, निगरानी और भुगतान प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों की अनदेखी की गई. उनका कहना है कि यदि निर्माण में निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल हुआ.

ग्रामीणों ने सरपंच-सचिव पर लगाया गंभीर आरोप

मामले में सरपंच राजकुमारी साकेत और सचिव शिव कुमार की भूमिका को लेकर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं. आरोप है कि निर्माण सामग्री की वास्तविक खरीद, मौके पर उपयोग और भुगतान अभिलेखों का मिलान किया जाना चाहिए. ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बिलों में सामग्री की मात्रा अथवा लागत वास्तविक उपयोग से अलग हो सकती है.

सड़क परिवहन मंत्रालय ने तैयार किया नया नियम

हेडलाइट में नहीं लगेगी हाईबीम

ग्वालियर, 29 अगस्त. सड़क परिवहन मंत्रालय ने हेडलाइट की पॉवर घटाने से लेकर शहरों में बेवजह हाईबीम पर ऑडियो अलर्ट तक का प्रपोजल रखा है. यानी आने वाले वक्त में सड़क पर सिर्फ गाड़ी चलाने के नियम नहीं बदलेंगे बल्कि गाड़ी की हेडलाइट और रोशनी भी बदल जायेगी.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की हेडलाइट और रात में उनकी बिजिबिलिटी से जुड़े नियमों से बड़े बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है. प्रपोजल के अनुसार दोपहिया वाहनों की मैक्सिमम हेडलाइट इंटेंसिटी को मौजूदा 1.5 लाख कैंडेला से घटाकर 1 लाख कैंडेला करने पर विचार किया जा रहा है. वहीं पैसेंजर कारों के लिये यह सीमा मौजूदा 2.25 लाख कैंडेला से घटाकर 1.5 लाख कैंडेला करने का प्रस्ताव है. इसका मकसद सामने से आने वाले वाहन के ड्राइवर की आंखों पर पड़ने वाली तेज रोशनी को कम करना है. खासकर रात में ड्राइविंग के दौरान, सरकार वाहन की हैडलाइट के कलर टेम्परेचर का लेकर नियम सख्त करने की तैयारी में है.

छुआछूत से आज भी जूझ रहा देश

खड़गे से जुड़े शुद्धिकरण पर राहुल हमलावर

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 29 अगस्त. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि देश में आज भी छुआछूत कायम है.

कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने कहा कि संविधान ने दलितों के खिलाफ भेदभाव और अत्याचार को गैरकानूनी बनाया है, लेकिन आज भी कई जगह दलित बच्चों से स्कूलों में शौचालय साफ कराने और झाड़ू-पोंछा लगाने जैसे काम कराए जाते हैं. बच्चों के मन पर गहरा असर पड़ता है. कुछ बच्चे अपने

साथियों को सफाई करते देखते हैं, जबकि सफाई करने वाले बच्चे देखते हैं कि उनके कुछ साथी ऐसे काम नहीं करते. कुछ जगह दलितों को सार्वजनिक कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं होती और उन्हें अपने लिए अलग कुआं खोदना पड़ता है. राहुल ने उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े 'शुद्धिकरण' कार्यक्रम का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.

इंदौर में 12 को छात्रों की गूंज

इंदौर. इंदौर में लोकसभा में विपक्ष नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम 12 सितंबर को होगा. इसके लिए शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम आयुक्त को नेहरू स्टेडियम के लिए आवेदन किया है.

झटका | दिवालिया केस में एनसीएलटी के फैसले से लेनदारों को लगा बड़ा झटका

22 हजार करोड़ कर्ज, चंद्रा सिर्फ 6 .5 करोड़ देंगे

नवभारत नेटवर्क

नई दिल्ली, 29 अगस्त. जी ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा की व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने बड़ा फैसला सुनाया है. ट्रिब्यूनल ने उनकी रिपेमेंट योजना को मंजूरी दे दी है. इसके तहत करीब 22,006.57 करोड़ रुपये के स्वीकृत दावों के मुकाबले लेनदारों को लगभग 6.5 करोड़ रुपये मिलेंगे.

यानी लेनदारों को करीब 99.97 प्रतिशत का हेयरकट स्वीकार करना होगा. सरल शब्दों में कहें तो हर 100 रुपये के दावे पर करीब तीन पैसे की वसूली होगी. एनसीएलटी का यह फैसला दो सदस्यीय पीठ के बंटे हुए फैसले के बाद आया. मामले को तीसरे सदस्य निलेश शर्मा के पास भेजा गया था. उन्होंने दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की धारा 114 के तहत रिपेमेंट योजना को मंजूरी दी. योजना का कई लेनदारों ने विरोध किया था. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी इसे बेहद कम रिकवरी वाला प्रस्ताव बताते हुए आपत्ति जताई. कंपनी का करीब 1,322.39 करोड़ रुपये का दावा था, जबकि उसे प्रस्तावित भुगतान महज करीब 38 लाख रुपये था. हालांकि, योजना के पक्ष में मतदान करने वाले लेनदारों के पास 80.81 प्रतिशत वोटिंग शेयर था. ट्रिब्यूनल ने माना कि वह बहुमत वाले लेनदारों के व्यावसायिक निर्णय को अपनी राय से नहीं बदल सकता.

तो और घट जाती देनदारी

एनसीएलटी ने यह भी माना कि चंद्रा की व्यक्तिगत संपत्तियों का अनुमानित मूल्य योजना के तहत प्रस्तावित रकम से काफी कम था. ऐसे में योजना खारिज होने और उन्हें दिवालिया घोषित किए जाने की स्थिति में लेनदारों को इससे भी कम राशि मिलने की संभावना थी. मामले की शुरुआत एक 170 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ी है, जिसकी सुभाष चंद्रा ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी.

खाप का वर्चस्व तोड़ने मुखर हो रहे जेन-जी

हरियाणा में प्यार और रिश्तों पर नई पीढ़ी का विद्रोह

चंडीगढ़, 29 अगस्त. हरियाणा में खाप पंचायतों के सामाजिक फरमानों को लेकर नई पीढ़ी और पारंपरिक व्यवस्था के बीच बहस छिड़ गई है.

राज्य की कुछ खाप पंचायतों ने गांवों के समूह या समान सामाजिक पृष्ठभूमि के भीतर प्रेम विवाह के खिलाफ अपना रुख दोहराया है. इसके साथ ही लिव-इन संबंधों और समलैंगिक रिश्तों को लेकर भी आपत्ति जताई गई है. इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों को संबंधित गांवों में प्रवेश से रोकने की बात कही गई है. इन फरमानों के बाद सोशल मीडिया पर युवाओं के अलग -अलग विचार सामने आ रहे हैं. जेन-जी से जुड़े एक वर्ग का कहना है कि दो सहमति देने वाले वयस्कों को अपने जीवनसाथी और निजी रिश्तों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए.